पश्चिम भोपाल बायपास : दूरी 5 .29 किमी कम

लागत 243 .86 करोड़ बढ़ी, कैबिनेट ने दी परियोजना के लिए संशोधित राशि की मंजूरी

03 साल में बढ़ गई लागत

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 1 सितंबर. पश्चिम भोपाल बायपास की लागत पिछले तीन वर्ष में 243.86 करोड़ रुपए बढ़ गई है, वहीं नए अलाइनमेंट के हिसाब से दूरी 5.29 किमी घट गई है.

दूरी घटने के बाद भी लागत बढ़ गई है. इस बढ़े हुए लागत पर मंगलवार को कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. ये वेस्टर्न बायपास 4 लेन मय पेव्ड शोल्डर होगा.

इस बायपास की लंबाई 35.61 किमी होगी. इसे हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल के तहत बनाया जाएगा, जिस पर अब 3,225 करोड़ 51 लाख रुपये खर्च होंगे. इसके अतिरिक्त जमीन अधिग्रहण आदि कामों के लिए भी 548 करोड़ 29 लाख रुपये का भुगतान भी राज्य बजट से किया जाएगा. इस बायपास के निर्माण से जबलपुर और नर्मदापुरम की ओर से इन्दौर आने-जाने वाले वाहनों को भोपाल से नहीं गुजरना पड़ेगा और 21 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी.

यहां बता दें कि पहले इस सड़क की लंबाई-40.90 किमी होनी थी, जिसके लिए 2,981 करोड़ 65 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति 4 सितंबर 2023 को प्रदान की गई थी. इस तरह तीन वर्ष में लागत नए अलाइनमेंट के हिसाब से 243 करोड़ 86 लाख रुपए बढ़ गई है. पश्चिम भोपाल बायपास का एक रेखण भोपाल-जबलपुर मार्ग पर मण्डीदीप के समीप इटायाकलां से प्रारंभ होकर भोपाल-देवास मार्ग के ग्राम फंदा के समीप तक निर्मित किया जाना था, जिसकी लंबाई-40.90 कि.मी. थी. पश्चिम भोपाल बॉयपास क्षेत्र में रातापानी टाईगर रिजर्व घोषित हो जाने, बड़े तालाब के कैचमेंट क्षेत्र में पर्यावरण विभाग के नोटिफिकेशन के प्रभाव का समावेश करने, राज्य पुरातत्व विभाग की प्राचीन धरोहर शिवमंदिर समसगढ़ एक रेखण पर आने तथा बॉयपास को पूर्वी बॉयपास से जोड़कर संपूर्ण रिंग रोड बनाने के कारण एकरेखण में परिवर्तन किया गया. एक रेखण में परिवर्तन से परियोजना की लागत में पूर्व स्वीकृति से 8.18 प्रतिशत बढ़ोतरी हो गई है.

मेहलुआ-बीना-खिमलासा मार्ग होगा फोरलेन

कैबिनेट ने मेहलुआ-बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग लंबाई 67.116 कि.मी., 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर के साथ हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल पर निर्माण के लिए कुल परियोजना वित्तीय लागत रूपये 2,776 करोड़ 83 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी है. भू-अर्जन पर 428 करोड़ 94 लाख रूपये तथा सुपरविजन चार्जेस पर भी 65 करोड़ 77 लाख रूपये खर्च होंगे. परियोजना निर्माण लागत रूपये 1,151 करोड़ है.

5 राज्यों को 1183 करोड़ की वित्तीय मंजूरी

शिवराज ने कृषि विकास योजनाओं को दी दूसरी मदर सैंक्शन

नई दिल्ली, 1 सितंबर. किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को आधुनिक सुविधाओं से मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने पांच राज्यों को 1,183.11 करोड़ रुपये की बड़ी वित्तीय मंजूरी दी है.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और त्रिपुरा के कृषि मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना के तहत दूसरी मदर सैंक्शन जारी करने की मंजूरी दी गई.

आंध्र प्रदेश को सबसे अधिक 409.40 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 296.09 करोड़ और कृषोन्नति योजना के तहत 113.31 करोड़ रुपये शामिल हैं. तमिलनाडु को कुल 355.88 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिसमें 251.79 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और 104.09 करोड़ रुपये कृषोन्नति योजना के तहत हैं.

> शिवराज ने राज्यों में कृषि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और धनराशि के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया. आंध्र प्रदेश में 'प्रति बूंद अधिक फसल' और कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की गई. तमिलनाडु में सूक्ष्म सिंचाई और तिलहन उत्पादन से जुड़े प्रयासों को रेखांकित किया गया. ओडिशा में कृषि यंत्रीकरण और कृषि विस्तार के लिए फंड के उपयोग को प्रभावी बताया गया.

एक नजर में

पिकअप की टक्कर से पत्नी की मौत, पति घायल

जबलपुर. खमरिया थाना अंतर्गत उमरिया खमरिया मेन रोड पर तेज रफ्तार लोडिंग पिकअप ने पैदल चल रहे पति-पत्नी को सामने से जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में 22 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया. दुर्घटना के बाद आरोपी चालक अपनी गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया. अनूप उर्फ अंकित धान (27) और उसकी पत्नी निर्जला चौधरी उर्फ महिमा (22) दोनों निवासी उमरिया पैन्टीकोस्टल चर्च खमरिया से प्रार्थना कर साइकिल से घर लौट रहे थे. मेन रोड पर वे साइकिल से उतरकर पैदल चलने लगे. इसी दौरान पिकअप टक्कर मार दी.

सपा से सीट बंटवारे का मोर्चा प्रमोद तिवारी को

लखनऊ. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले. उनके साथ उनकी बेटी और कांग्रेस विधायक दल की नेता अनुराधा मिश्रा भी थीं. गौरतलब है कि यूपी में कांग्रेस के दो ही विधायक हैं, जिनमें एक प्रमोद तिवारी की बेटी हैं. प्रमोद तिवारी भले प्रदेश अध्यक्ष नहीं हैं लेकिन उनको उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा माना जाता है. पार्टी के शीर्ष नेताओं को उनके ऊपर भरोसा है. इसलिए अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या वे समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल पर चर्चा कर रहे हैं?

नितिन नबीन से मिले सीएम डॉ. यादव

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 1 सितंबर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में मंगलवार को सांसद एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से सौजन्य भेंट की.

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव और नितिन नवीन के बीच समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने नबीन को मध्यप्रदेश में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति और गतिविधियों की जानकारी दी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं जनोन्मुखी बनाने के लिए किए जा रहे नवाचारों और प्रयासों से भी नबीन को अवगत कराया.

इस मुलाकात का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि ओरछा में दो दिनी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक हुई है. कार्यसमिति की बैठक शुरू होने से ठीक पहले सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की थी और अब कार्यसमिति की बैठक समाप्त होने के अगले ही दिन वे नई दिल्ली पहुंचें और यहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले.

200 किमी की पदयात्रा शुरू

यूजीसी के नियमों का विरोध

नवभारत न्यूज

भिंड, 1 सितंबर. विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों के विरोध में श्री राजपूत करणी सेना ने मंगलवार से 200 किमी की पदयात्रा शुरू की. पदयात्रा बाइपास स्थित महाराणा प्रताप प्रतिमा से शुरू हुई और 11 सितंबर को ग्वालियर पहुंचेगी.

पदयात्रा फूप, सुरपुरा, अटेर मोड़, अंगदपुरा, सौरा-मौरा, पावई, पिथनपुरा, नुन्हाड़, सुनारपुरा, गोरमी, पोरसा, अंबाह, दिमनी, मुरैना और बानमौर होते हुए ग्वालियर पहुंचेगी. कार्यकर्ता रोजाना 20 से 25 किमी पैदल चलेंगे. राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना भी यात्रा में शामिल होंगे. सवर्ण समाज से यात्रा को समर्थन मिल रहा है.

करणी सेना ने कहा कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ संगठन आगामी निकाय, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में विरोध करेगा. उन्होंने कहा कि यूजीसी के मुद्दे पर चुप रहने वाले सवर्ण समाज के नेताओं का भी संगठन विरोध करेगा. इस दौरान संभागीय अध्यक्ष कुलदीप प्रताप भदौरिया, जिलाध्यक्ष रिशु भदौरिया, अमन शर्मा और सत्यम भदौरिया मौजूद रहे.

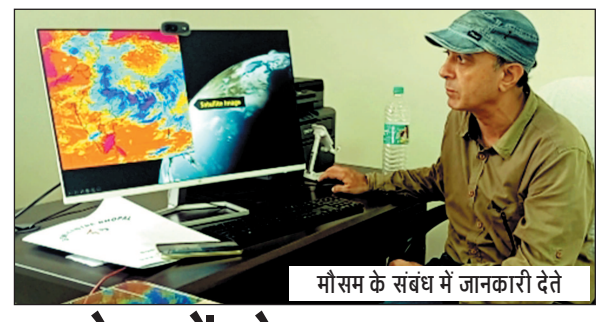

मौसम के संबंध में जानकारी देते

प्रदेश में दोबारा मानसून सक्रिय, ब्रेक के संकेत नहीं

05 दिन अलग-अलग हिस्सों में तेज बारिश का दौर

नवभारत न्यूज

भोपाल, 1 सितम्बर. मध्यप्रदेश में सितंबर की शुरुआत के साथ मानसून कमजोर पड़ने के बजाय दोबारा सक्रिय हो गया है. अगले पांच दिन प्रदेश में बारिश का कोई लंबा ब्रेक मिलने के संकेत नहीं हैं. हालांकि, पूरे प्रदेश में एक साथ तेज बारिश नहीं होगी. हर दिन इसका मुख्य क्षेत्र बदलता रहेगा.

मंगलवार को पूर्वी मध्यप्रदेश, बुधवार को पूर्वी और मध्य हिस्से, गुरुवार को उत्तर-मध्य तथा शुक्रवार को पश्चिमी जिलों में तेज बारिश की संभावना है. बीते 24 घंटों में रीवा, शहडोल और सागर संभाग में मानसून सबसे अधिक सक्रिय रहा. रामपुर बाघेलान में 123.6 मिमी और बीरसिंहपुर में 115.6 मिमी के साथ अति भारी बारिश दर्ज हुई. मझगांव में 78 मिमी, रीवा में 71 मिमी, ब्योहारी में 67 मिमी तथा जवा में 65 मिमी के साथ भारी बारिश हुई. मैहर में 52.2 मिमी, सतना में 48.3 मिमी, जयातपुर में 44 मिमी और अमरपाटन में 43 मिमी पानी गिरा. वहीं इंदौर, ग्वालियर और चंबल संभाग के अधिकतर इलाकों में मौसम सूखा रहा. आगामी 24 घंटों में सीधी, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, सिवनी, मंडला, पन्ना में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है. विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, सिंगरौली, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, दमोह, सागर और छतरपुर में भारी बारिश हो सकती है.

> भोपाल, सीहोर, राजगढ़, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और पांढुर्णा में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. मध्यप्रदेश में 1 जून से अब तक की 707.1 यानी 27.83 मिमी बारिश दर्ज की गयी है को की सामान्य 791.7 मिमी यानि 31.16 इंच से 11 प्रतिशत कम मापी गयी गयी है.

प्रदेश में एक माह चलेगा सेवा संकल्प अभियान

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 1 सितंबर.मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आगामी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जनसेवा के 25 साल पूरे हो रहे हैं.

इन 25 सालों में विकास और जनकल्याण के जो अविस्मरणीय कार्य हुए हैं, उनकी जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा. यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से प्रारंभ होकर एक माह अर्थात 17 अक्टूबर तक चलेगा. सेवा संकल्प अभियान विकसित भारत के संकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा. इस अभियान के तहत अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रियों से अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सांस्कृतिक उत्थान और धार्मिक पर्यटन की जो दृष्टि प्रदान की, उसी के परिणामस्वरूप प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हमारी गौरवशाली परम्परा और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने का कार्य आरंभ किया गया है. इस दिशा में प्रदेश में 243 करोड़ रूपए की लागत से विभिन्न संरक्षण और विकास कार्य जारी हैं.

बीच सड़क पर रील बनाना पड़ा भारी

युवक ने वीडियो जारी कर मांगी माफी

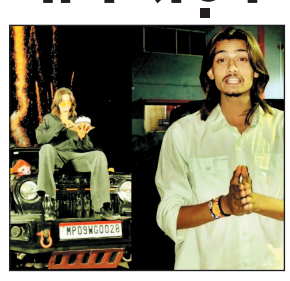

नवभारत न्यूज

इंदौर, 1 सितंबर. सोशल मीडिया पर रील बनाकर पब्लिसिटी पाने के चक्कर में रक्षाबंधन की रात बीच सड़क थार खड़ी कर बोनट पर केक काटना युवक को भारी पड़ गया. 28 अगस्त की रात बनाए गए वीडियो के वायरल होने के बाद जूनी इंदौर पुलिस ने वाहन की पहचान कर कार्रवाई की.

पुलिस की कार्रवाई के बाद युवक ने वीडियो जारी कर अपनी गलती के लिए माफी मांगी. घटना 28 अगस्त की है. थार को सड़क के बीच खड़ा कर बोनट पर केक काटा था. इसी दौरान रील बनाई गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में युवक और उसके साथ मौजूद लोगों की गतिविधियों को लेकर भी आपत्ति जताई गई. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू की. घटना स्थल को लेकर शुरुआती तौर पर थाना क्षेत्र की स्थिति स्पष्ट नहीं थी. जूनी इंदौर थाना क्षेत्र से संबंधित पाए जाने के बाद पुलिस ने थार की पहचान की. वाहन का विधिवत चालान काटा. साथ ही वाहन स्वामी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आर्यन के खिलाफ कार्रवाई की गई.

बख्शा नहीं जाएगा : डीसीपी

मामले में अतिरिक्त डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि सड़क पर हुड़दंग कर रील बनाने और यातायात प्रभावित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. आम लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा.

चिकित्सक समय पर उपस्थित रहें : शुक्ल

उपमुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

भोपाल, 1 सितंबर. उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न विषयों की समीक्षा की. उन्होंने विभागीय व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने तथा आमजन को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए.

उपमुख्यमंत्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक निर्धारित समय पर उपस्थित रहें, इसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निगरानी व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से लागू की जाएं. चिकित्सकों की उपस्थिति एवं कार्यप्रणाली की नियमित निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

उन्होंने विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए. बैठक में विभाग में अन्य रिक्त पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई. उप मुख्यमंत्री ने आवश्यकतानुसार भर्ती प्रक्रिया को गति देने और मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. बैठक में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा सुखवीर सिंह, आयुक्त धनराजू एस उपस्थित रहे.

किताबों को वाहन में लोड कराने प्रधानाध्यापक सस्पेंड

सीधी. शासकीय माध्यमिक विद्यालय चुवाही की पुस्तकों को विद्यार्थियों के माध्यम से वाहन में लोड कराने के मामले में कलेक्टर विकास मिश्रा ने प्रभारी प्रधानाध्यापक मनोज कुमार वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. पुस्तकों को वाहन में लोड कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले की जांच कराई गई थी. जांच प्रतिवेदन के आधार पर जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब को असंतोषजनक पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई. आदेश में कहा गया है कि बिना सक्षम अनुमति एवं भौतिक सत्यापन के विद्यालय की उपयोगी व अनुपयोगी पुस्तकों को वाहन में लोड कराना कदाचरण की श्रेणी में आता है.

मूल निवासी छात्रों को नहीं मिल रही स्कॉलरशिप

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकार सहित अन्य से मांगा जवाब

नवभारत न्यूज

जबलपुर, 1 सितंबर. केन्द्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गयी पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि प्रदेश सरकार द्वारा मूल निवासी छात्रों को नहीं प्रदान करने का आरोप लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी थी.

सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए केन्द्र व राज्य सरकार सहित राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता डॉ. दिनेश चंद्र पाटीदार की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार ने 2014-15 में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट-ग्रेजुएशन लेवल पर पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की थी. इस स्कीम के तहत प्रदेश के मूल निवासी छात्र देश के किसी भी राज्य में पढ़ाई कर सकते हैं. पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स के तीन सालों की फीस केन्द्र सरकार द्वारा यह राशि राज्य सरकार के माध्यम से प्रदेश के मूल निवासी छात्रों को प्रदान की जायेगी.

हर साल 7 लाख रुपए फीस जमा की

याचिका में कहा गया था कि उसने ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के रूप मध्य प्रदेश से बीडीएस का कोर्स किया था. इसके बाद एमडी कोर्स के लिए उसने अंबाला हरियाणा में एडमिशन लिया. हरियाणा के मेडिकल कॉलेज में उन्होंने हर साल 7 लाख रुपये फीस जमा की थी. केन्द्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गयी पोस्ट- मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के कमिश्नर से अनुरोध किया, तो उन्हें हर साल 42,000 रुपये के हिसाब से दो साल में कुल 84 हजार रूपये प्रदान किये गये. जिसके खिलाफ उसने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली गयी है.

मप्र में जुआ-सट्टा पर पुलिस का शिकंजा

भोपाल. मध्यप्रदेश पुलिस ने अगस्त माह के दौरान अवैध जुआ और सट्टा गतिविधियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाते हुए विभिन्न जिलों में कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 1.10 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की नकदी और अन्य संपत्ति जब्त की तथा बड़ी संख्या में आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की. पुलिस ने अपने सूचना तंत्र, निगरानी व्यवस्था और मैदानी कार्रवाई के माध्यम से जुआ फड़ों एवं सट्टा कारोबार से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया. कार्रवाई के दौरान नकदी, मोबाइल फोन, वाहन, लैपटॉप, एटीएम कार्ड, वाई-फाई मॉडम तथा अन्य उपकरण जब्त किए गए.

बयान | प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल

भ्रष्टाचार पर नहीं है 'जीरो टॉलरेंस'

विशेष संवाददाता

भोपाल, 1 सितंबर. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश में कथित रूप से बढ़ते भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में बेहद कम दोषसिद्धि दर को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीति भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नहीं, बल्कि 'जीरो एक्शन' की दिखाई दे रही है.

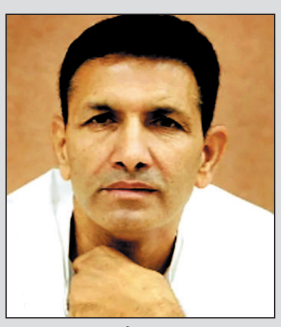

एक प्रेस बयान में जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार अब केवल एक समस्या नहीं रह गया है, बल्कि यह एक ऐसे 'कैंसर' का रूप ले चुका है, जो पूरी सरकारी व्यवस्था को कमजोर कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्ट अधिकारियों ने जनसेवा के लिए मिले पदों को व्यक्तिगत आय का सुरक्षित माध्यम बना लिया है.

लोकायुक्त के आंकड़ों का हवाला देते हुए पटवारी ने कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़े 1,063 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, लेकिन इनमें केवल सात मामलों में दोषसिद्धि हो सकी. उन्होंने कहा कि यह दोषसिद्धि दर महज 0.65 प्रतिशत है. पटवारी ने कहा कि ये आंकड़े केवल भ्रष्ट अधिकारियों पर ही नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं, जो भ्रष्टाचार की पहचान तो करती है, लेकिन दोषियों को सजा तक पहुंचाने में कथित रूप से विफल रहती है.

> **भ्रष्टाचार के खिलाफ डर हो रहा है खत्म**
>
> उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई और अभियोजन स्वीकृति में होने वाली देरी भ्रष्टाचार के खिलाफ डर को खत्म कर रही है और आरोपियों को संरक्षण देने का काम कर रही है. पटवारी ने लंबित मामलों में शीघ्र कार्रवाई, अभियोजन स्वीकृति में देरी समाप्त करने तथा कानून के तहत दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की.

छिंदवाड़ा में कार से 25 पेटी शराब बरामद

छिंदवाड़ा. जुन्नारदेव थाना पुलिस ने कार से 25 पेटियों में भरी 215.82 बल्क लीटर शराब बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख 45 हजार 950 रुपये बताई गई है. पुलिस ने करीब सात लाख रुपये कीमत की कार और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है. मामले में एक महिला सहित दो आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया. पुलिस के अनुसार सोमवार की रात सूचना मिली थी कि पालाचैरई अंबाड़ा की ओर से विजय उर्फ गुड्डा वसूले निवासी माईरी अपनी कार में बड़ी मात्रा में देशी-विदेशी शराब लेकर घर की ओर आ रहा है. पुलिस टीम ने विजय के घर के सामने कार को रोकने का प्रयास किया.

विजय शाह के खिलाफ की जाए कार्रवाई

विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्यपाल से की मांग

विशेष संवाददाता

भोपाल, 1 सितंबर. मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस के एक विधायक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात कर मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में अभियोजन के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की मांग की.

प्रतिनिधिमंडल में विधायक आरिफ मसूद और सुरेश राजे भी शामिल थे. प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए मंत्री के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की. मुलाकात के बाद उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि उक्त टिप्पणी कर्नल सोफिया कुरैशी, सशस्त्र बलों, महिलाओं और देश का अपमान है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब मंत्रिमंडल को अभियोजन की अनुमति देने और किसी मंत्री को पद से हटाने का अधिकार है तो राज्य सरकार इस मामले में राज्यपाल को क्यों शामिल कर रही है.

सिंघार ने भाजपा सरकार पर महिलाओं के प्रति अपनी घोषित प्रतिबद्धता और इस विवाद पर उसके रुख में अंतर होने का आरोप भी लगाया.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60